NYCS

युवा सहकार

www.nycsindia.com

नवंबर 2024, नई दिल्ली

दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार

भारत

युवा निभाएंगे अहम भूमिका

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

facebook.com/kribhco.pr @kribhco_pr @kribhco5573

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-05, नवंबर-2024

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं पारस ऑफसेट प्रा. लि. कुंडली, हरियाणा द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

दौड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगी दुनिया 04

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में बनेंगे एआई केंद्र 05

06 दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार भारत

11 कृषि अब भी रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम

मैन्यूफैक्चरिंग : नौ दिन चले अढ़ाई कोस 12

दुनिया सुनेगी भारतीय सहकारिता की गूंज 15

स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल हो सहकारिता 16

विश्व की कौशल राजधानी बनेगा भारत 18

श्वेत क्रांति 2.0 से डेयरी क्षेत्र का होगा कायाकल्प 20

सहकारिता की चुनौतियां और भविष्य 22

सहकारिता के प्रयोग से झारखंड में बदला जीवन 24

दोगुने मुद्रा लोन से बढ़ेगा स्वरोजगार 27

मेरा युवा भारत: युवाओं का बढ़ेगा सामर्थ्य 29

दौड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगी दुनिया

यह सच है कि बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था में बहुत से बदलाव आए हैं और इसका आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र बढ़ेगा तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने और उसे बढ़ाने के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है। हालांकि, भारत अपनी चुनौतियों को समझ भी रहा है और प्रगति का रास्ता भी बना रहा है।

कोविड महामारी से चरमराई वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में देश की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह से तेज उड़ान भरी उससे अब पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिक गई हैं। पिछले तीन-चार साल में भारत की विकास दर 7-8 प्रतिशत रही है। दुनिया के विकसित देशों की विकास दर भी इसके आसपास फटक नहीं पाई है। इस रफ्तार को हासिल करने और इसे आगे बढ़ाने में युवाओं का प्रमुख योगदान रहा है। युवाओं के सामर्थ्य के बूते ही भारत ने 2047 तक विकसित देशों की कतार में खड़ा होने का लक्ष्य रखा है।

सरकार भारतीय युवाओं की एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटी है जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके। इसलिए, एजुकेशन, स्किल डवलपमेंट, रिसर्च, इंप्लॉयमेंट पर सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। वैश्विक समुदाय भारत को शिक्षा, कौशल, हेल्थकेयर और सॉफ्टवेयर विकास में व्यापक अवसरों के साथ मानव संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है। भारत के युवाओं को इन अवसरों के लिए तैयार करने के लिए सरकार उनके कौशल को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ रही है।

आज भारत हर सेक्टर में जिस तेजी से काम कर रहा है उसकी वजह से विकासशील देश से आगे बढ़कर उभरती हुई शक्ति बन गया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत यूं ही दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार नहीं है, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत की स्थिति नंबर एक से लेकर नंबर पांच तक है। इनमें दूध, फल एवं सब्जियों, दवा एवं वैक्सीन उत्पादन, मोबाइल हैंडसेट का निर्माण एवं डाटा के इस्तेमाल और फिनटेक अपनाने से लेकर रेल एवं सड़क नेटवर्क तैयार करने, तेल एवं गैस रिफाइनरी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टार्टअप इकोसिस्टम, कोयला, थोरियम एवं लौह अयस्क का भंडार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

भारत अभी दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था है और आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2047 तक भारत ने 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लिया है। इसके लिए मैन्यूफैक्चरिंग जीडीपी ग्रोथ को 15 गुना बढ़ाकर 6.2 ट्रिलियन डॉलर और सर्विस सेक्टर जीडीपी को 13 गुना बढ़ाकर 20 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाना होगा। मगर यही सबसे बड़ी चुनौती है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को 15-16 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 25 प्रतिशत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया का जो अभियान चलाया था उसका अपेक्षित नतीजा नहीं मिला। यह सच है कि बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था में बहुत से बदलाव आए हैं और इसका आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है। यह 17 प्रतिशत के आसपास ही घूम रही है। इसका असर रोजगार पर पड़ रहा है। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र बढ़ेगा तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने और उसे बढ़ाने के मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियों का अंबार है जिसके समाधान का प्रयास सरकार तो कर रही लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। हालांकि, भारत अपनी चुनौतियों को समझ भी रहा है और प्रगति का रास्ता भी बना रहा है।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में बनेंगे एआई केंद्र

युवा सहकार टीम

केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी की मौजूदगी में मेटा से हुआ एमओयू।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के माध्यम से भारतीय युवाओं का कौशल विकास करने के लिए दिग्गज अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा (पहले फेसबुक) आगे आई है। इस संबंध में मेटा का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) से ज्ञापन समझौता (एमओयू) हुआ है। इस साझेदारी के तहत एआई में सहयोग के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और मिक्स्ड रियलिटी (एमआर) में मेटा की ओर से पांच उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में ये उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।

इस साझेदारी पर केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने कहा 'हमारा मिशन भारत के युवाओं को आज के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सफलता के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जैसी तकनीकों को कौशल भारत तंत्र में एकीकृत करके हम युवाओं के लिए व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग को सक्षम करने वाली अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहे हैं। मेटा के साथ साझेदारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'

इस साझेदारी के तहत मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल द्वारा संचालित एक एआई-चैटबॉट विकसित किया जाएगा, जो स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) पोर्टल पर शिक्षार्थियों के अनुभव को बढ़ाएगा। एसआईडी पोर्टल में एकीकृत किया जाने वाला चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे सहायता प्रदान करता है। इससे पाठ्यक्रम की जानकारी की खोज, पाठ्यक्रम सामग्री के लिए इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर और संशोधन के लिए व्याख्यान

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से हुआ मेटा का एमओयू। हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में खोले जाएंगे उत्कृष्टता केंद्र

सारांश और प्रासंगिक वीडियो तक पहुंच संभव हो पाती है। व्हाट्सएप पर उपलब्ध चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी और हिंग्लिश के साथ-साथ वॉयस क्षमताओं को सक्षम बनाएगा जिससे यह पूरे देश के विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा, उपयोगकर्ता विशिष्ट पाठ्यक्रम विषयों की खोज कर सकते हैं, कौशल केंद्रों के बारे में जानकारी पा सकते हैं, स्थान और रुचि के आधार पर नौकरियों का पता लगा सकते हैं और निरंतर सुधार के लिए अनुरूप प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। मेटा का चैटबॉट कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय को सटीक विश्लेषण भी प्रदान करेगा।

मेटा ओपन सोर्स एआई मॉडल भारत के एआई तंत्र को सुलभ बनाकर भारत के एआई मिशन के अनुरूप बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले एआई समाधानों को अपनाने के लिए एक सहयोगी ई-गवर्नेंस ढांचे की परिकल्पना है। एआई असिस्टेंट में सहयोग के लिए साझेदारी का उद्देश्य सूचना तक लोगों की पहुंच को सुव्यवस्थित करना, सीखने के परिणामों में सुधार करना और छात्रों को सहज डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से निर्बाध सहायता प्रदान करना है। उत्कृष्टता केंद्र वास्तविक सिमुलेशन प्रदान करने के साथ युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाएंगे।

मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति प्रमुख शिवनाथ ठुकराल ने कहा, "हम भारत के आर्थिक विकास में सार्थक प्रभाव पैदा करने के लिए एआई, वीआर और एमआर जैसी अग्रणी तकनीकों का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ ये साझेदारी प्रौद्योगिकी और शिक्षा के बीच अंतर को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ओपन सोर्स लामा जैसी उन्नत तकनीकों के एकीकरण के माध्यम से हमारा लक्ष्य न केवल छात्रों को बल्कि शिक्षकों और उद्यमियों को भी सशक्त बनाना है, उन्हें आज की डिजिटल-फर्स्ट दुनिया में कामयाब होने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना है।"

दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार भारत

हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं, जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके। इसलिए, एजुकेशन, स्किल डवलपमेंट, रिसर्च, इंप्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, उनके नतीजे मिलने लगे हैं।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

युवा सहकार टीम

युवाओं के कंधों पर सवार भारत की अर्थव्यवस्था ने महामारी के बाद जिस रफ्तार से उड़ान भरी है, उससे पूरी दुनिया चकित है। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश अभी भी महामारी के दौर की सुस्ती से उबर नहीं पाए हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव (इजरायल का फिलस्तीन, लेबनान और ईरान से संघर्ष) और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच शांतिदूत बने भारत ने विकास की रफ्तार को बरकरार रख कर यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया अब भारत की ओर टकटकी लगाए हुए है। विकास की रफ्तार को बनाए रखने और इसे आगे बढ़ाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है।

देश की युवा शक्ति पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सम्मेलन में कहा, 'हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं, जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके। इसलिए, एजुकेशन, स्किल डवलपमेंट, रिसर्च, इंप्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, उनके नतीजे मिलने लगे हैं। भारत दुनिया का वह देश है जहां रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे अधिक सुधार हुआ है। आज भारत दुनिया के लिए रिसर्च एवं डवलपमेंट का बड़ा हब बनता जा रहा है। दुनिया की करीब ढाई हजार कंपनियों के रिसर्च सेंटर भारत में हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी यहां अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है।'

आज भारत हर सेक्टर में जिस तेजी से काम कर रहा है उसकी वजह से विकासशील देश से आगे बढ़कर उभरती हुई शक्ति बन

गया है और 1947 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने का संकल्प लिया है। गरीबी की चुनौतियों से निपटते हुए प्रगति का रास्ता बनाने के लिए सरकार जो नीतियां बना रही है और जो सुधार कर रही है, उसकी बदौलत भारत ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़ते हुए दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत यूं ही नहीं दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने को तैयार है, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत की स्थिति नंबर एक से लेकर नंबर पांच तक है।

ग्लोबल कमर्शियल रियल एस्टेट एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी जेएलएल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जबकि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क और चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दूध उत्पादन, वैक्सीन उत्पादन, प्रति मोबाइल फोन में प्रति महीने डाटा इस्तेमाल और फिनटेक को अपनाने के मामले (दुनिया में 87 प्रतिशत) और थोरियम के भंडार के मामले में भारत नंबर वन है। इसी तरह, भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम, कोयले के भंडार, मोबाइल हैंडसेट निर्माण और फल एवं सब्जियों के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल एवं गैस रिफाइनर है। फार्मा इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मात्रा के हिसाब से भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही, केमिकल उत्पादन के मामले में एशिया में तीसरे स्थान पर है। जेएलएल की रिपोर्ट कहती है कि लौह अयस्क के भंडार, रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता और रक्षा बजट के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है।

2047 में आजादी के सौ साल पूरे होने तक भारत ने खुद को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। भारत का लक्ष्य है कि इस समय तक 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए मैन्यूफैक्चरिंग जीडीपी ग्रोथ को 15 गुना बढ़ाकर 6.2 ट्रिलियन डॉलर और सर्विस सेक्टर जीडीपी को 13 गुना बढ़ाकर 20 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाया जाए। इस समय तक विदेशी निवेश को 12 गुना बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर और निर्यात को 12 गुना की तेजी के साथ 8 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाया जाए। हालांकि वर्ष 2024 में देश की अर्थव्यवस्था का आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले ढाई दशक में करीब 28 ट्रिलियन डॉलर के अंतर को पाटना होगा। जेएलएल की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकास की उम्मीदें हैं और जिनसे भारत को फायदा मिल सकता है, उनमें इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज, फार्मा और सेमीकंडक्टर सेक्टर शामिल हैं।

दुनिया की उम्मीदें भारत से कितनी हैं इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल के तीन-चार महीनों में भारत में कई ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं। इनमें टेलीकॉम

दुनिया में भारत की स्थिति

1 दूध उत्पादन, वैक्सीन उत्पादन, प्रति महीने प्रति मोबाइल डाटा इस्तेमाल और फिनटेक अपनाने।

2 सड़क नेटवर्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मोबाइल हैंडसेट निर्माण, कोयले का भंडार, फल एवं सब्जियों का उत्पादन, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी। तेल एवं गैस क्षेत्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर।

3 उपभोक्ता बाजार, मात्रा के हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तीसरा बड़ा उत्पादक। केमिकल का एशिया में तीसरा बड़ा उत्पादक।

4 रेल नेटवर्क, रक्षा बजट, रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता और लौह अयस्क का भंडार।

5 दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था।

मौजूदा दौर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का है। एआई भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थकेयर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। भारत दुनिया को और बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटा है।

भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए मैन्यूफैक्चरिंग जीडीपी ग्रोथ को 15 गुना बढ़ाकर 6.2 ट्रिलियन डॉलर और सर्विस सेक्टर जीडीपी को 13 गुना बढ़ाकर 20 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाया जाए। इस समय तक निर्यात को 12 गुना की तेजी के साथ 8 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाया जाए।

और डिजिटल फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए हुई इंटरनेशनल असेंबली, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल, ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर इवेंट और रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल एविएशन के फ्यूचर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। यह सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, यह भारत से जुड़ी उम्मीद की भी लिस्ट है। इससे भारत की दिशा और दुनिया की आशा दोनों को समझा जा सकता है। ये वो विषय हैं जो आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगे और इन विषयों पर चर्चा के लिए दुनिया भारत आ रही है।

दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया महंगाई, बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज, युद्ध और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन बिखरने की चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल परिस्थितियों से भारत को फर्क नहीं पड़ता है, भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे सकारात्मक तरीके से निपटने के नए-नए रास्ते खोजे जा रहे हैं ताकि अवसरों का लाभ उठाया जा सके। भारत अपनी चुनौतियों को समझ भी रहा है और प्रगति का रास्ता भी बना रहा है। स्थिर और मजबूत सरकार की वजह से नीतियां बनाने, निर्णय लेने और सुधार करने में मदद मिल रही है।

इसकी वजह से पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 350 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं जिनमें 15 से ज्यादा एम्स हैं। पिछले 10 साल में भारत में डेढ़ लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप्स बने हैं और 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर स्वरोजगार शुरू किया है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। युवाओं की भरपूर क्षमता भारत को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकती है। आज भारत की सोच और अप्रोच में बदलाव आया है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, आगे का लक्ष्य क्या है और हमें कहां पहुंचना है। अब अप्रोच यह है कि कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है और कब तक पहुंचेंगे। अब भारत आगे देखने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है।

मौजूदा दौर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का है। एआई भारत के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि यह भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थकेयर, एजुकेशन, स्टार्टअप्स हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है।

टाटा समूह देगा 5 लाख नौकरियां

मेक इन इंडिया के तहत मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने से ही रोजगार की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। टाटा समूह ने अगले 5 साल में 5 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से भी लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये नौकरियां सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी), बैटरी और इससे जुड़े उद्योगों में दी जाएंगी। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने यह घोषणा करते हुए कहा कि देश का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर 7.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे वित्त वर्ष 2022-23 में करीब 13 लाख नौकरियां पैदा हुई।

टाटा संस के चेयरमैन ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा, 'हम भारत को विकसित देश बनाने का सपना देख रहे हैं। इसे पूरा करने में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस क्षेत्र में नौकरियां पैदा किए बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। हर महीने करीब 10 लाख लोग वर्कफोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए हमें देश के भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करनी होंगी।'

टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बड़े निवेश किए हैं और असम में एक बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है। इसके अलावा ईवी और बैटरी निर्माण में भी समूह काम रहा है। चंद्रशेखरन ने कहा कि समूह अगले 5 साल की योजना को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। इस दौरान 5 लाख नौकरियां देना हमारा लक्ष्य है। हालांकि, हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करने पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों के दौरान हमें 10 करोड़ नौकरियां उपलब्ध करानी हैं। अगर हम 5 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां देंगे, तो इनकी मदद से कई गुना अप्रत्यक्ष नौकरियां सामने निकलकर आएंगी। एनएसओ (नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑर्गनाईजेशन) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 11 लाख नौकरियां पैदा हुई थीं। मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का नंबर है।

भारत दुनिया को और बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटा है। भारत में हो रहा चौतरफा परिवर्तन दुनिया के भरोसे का आधार बन रहा है। दुनिया को लगता है कि भारत संकट के समय का साथी है। कोविड का वह दौर याद कीजिए जब इससे बचाने के लिए जरूरी दवाओं और वैक्सीन की दुनिया को जरूरत थी, खासकर विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों को। तब भारत ने मुनाफे का रास्ता त्याग कर मानवता का रास्ता चुना और दुनिया के सैकड़ों देशों को संकट के समय दवाई और जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाई। उस कठिन समय में भारत दुनिया के काम आ पाया।

स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस आज के युग की बड़ी जरूरतें हैं। भारत आज यही प्रयास कर रहा है। स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ-साथ भारत आज सॉल्यूशंस पर भी फोकस कर रहा है। बीते दशक में भारत ने ऐसे अनेक सॉल्यूशंस पर काम किया है जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, योग हो, आयुर्वेद हो, मिशन लाइफ हो, मिशन मिलेट्स हो, भारत द्वारा किए गए सभी प्रयास दुनिया की चुनौतियों के समाधान देने वाले हैं। भारत का बढ़ता सामर्थ्य दुनिया की बेहतरी को सुनिश्चित कर रहा है। भारत जितना आगे बढ़ेगा, दुनिया को उतना ही फायदा होगा। ■

दुनिया को लगता है कि भारत संकट के समय का साथी है। कोविड का वह दौर याद कीजिए जब इससे बचाने के लिए जरूरी दवाओं और वैक्सीन की दुनिया को जरूरत थी, खासकर विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों को। तब भारत ने मुनाफे का रास्ता त्याग कर मानवता का रास्ता चुना और दुनिया के सैकड़ों देशों को संकट के समय दवाई और जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाई।

भविष्य के भारत की उम्मीद

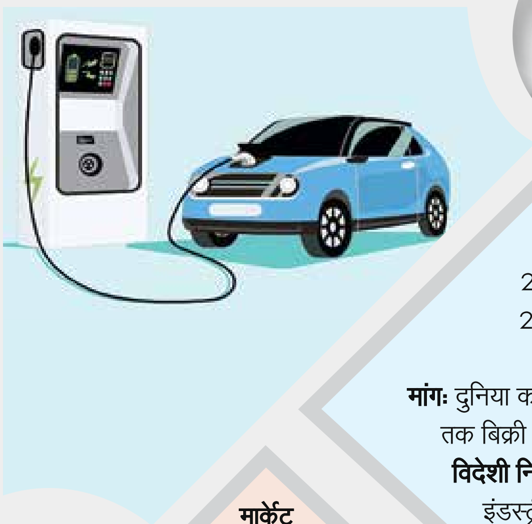

इलेक्ट्रिक वाहन

मार्केट साइज :
2021:- 100 अरब डॉलर
2027:- 160 अरब डॉलर (अनुमानित)

मांगः दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार वर्ष 2030 तक बिक्री 3.76 लाख/प्रतिमाह का अनुमान

विदेशी निवेशः वित्त वर्ष 2022-23 में ऑटो इंडस्ट्री में 190.2 करोड़ डॉलर का एफडीआई, कुल निवेश का 4.1 प्रतिशत

रिन्यूएबल एनर्जी

मार्केट साइज :
2022:- 20 अरब डॉलर
2028:- 35.6 अरब डॉलर (अनुमानित)

मांगः भारत ने कार्बन इंटेंसिटी को अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक के 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही इस समय तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% संचयी विद्युत क्षमता स्थापित करने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है

विदेशी निवेशः वित्त वर्ष 2022-23 में कार्बन इंटेंसिटी 250 करोड़ डॉलर का एफडीआई, कुल निवेश का 5.5 प्रतिशत

इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज

मार्केट साइज :
2023:- 77.19 अरब डॉलर
2030:- 124.94 अरब डॉलर (अनुमानित)

मांगः कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू मांग काफी तेजी से बढ़ रही है।

विदेशी निवेशः वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 53.99 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश, कुल विदेशी निवेश का 1.17 प्रतिशत

फार्मास्युटिकल्स

मार्केट साइज :
2021:- 41 अरब डॉलर
2030:- 130 अरब डॉलर (अनुमानित)

मांगः वैश्विक वैक्सीन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 60%, डब्ल्यूएचओ की 70% मांग पूरी करने का अनुमान साथ खसरे के टीके की 90% मांग पूरी करने का अनुमान

विदेशी निवेशः वित्त वर्ष 2022-23 में ड्रग्स एवं फार्मा क्षेत्र में 205.8 करोड़ डॉलर का एफडीआई, कुल एफडीआई का 4.5 प्रतिशत

सेमीकंडक्टर

मार्केट साइज
2023:- 23.2 अरब डॉलर
2028:- 80.3 अरब डॉलर (अनुमानित)

मांगः अभी भारत में सेमीकंडक्टर की पूरी मांग आयात से ही पूरी की जाती है

विदेशी निवेशः 2022 में सेमीकंडक्टर सेक्टर में 26.2 अरब डॉलर एफडीआई आया।

कृषि अब भी रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम

युवा सहकार टीम

केंद्र सरकार लगातार यह कोशिश करती रही है कि रोजगार के लिए कृषि पर से निर्भरता कम की जाए, मगर इसमें ज्यादा सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। नाबार्ड के ताजा सर्वे में यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियां देश में अब भी रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही हो, लेकिन लगता है कि तेज आर्थिक विकास का फायदा कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। शायद यही वजह है कि मूल्यों में भले ही अर्थव्यवस्था की गति कुलांचे भर रही है, लेकिन रोजगार के नए अवसर पैदा करने के मामले में पिछड़ रही है। नाबार्ड के सर्वे के मुताबिक, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर ग्रामीण आबादी की संख्या 48 प्रतिशत से बढ़कर 57 फीसदी पर पहुंच गई है।

नाबार्ड ने यह सर्वे जुलाई 2021 से जून 2022 के बीच किया था। देश उस वक्त कोविड काल से गुजर रहा था और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अपने गांव लौट गए थे। सर्वे में नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ 50 हजार तक की आबादी वाले अर्द्ध शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया था। सर्वे में 6,500 रुपये से अधिक की मासिक कृषि आय वाले परिवारों को शामिल किया गया था। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के जरिये जीवनयापन कर रहे ग्रामीण परिवारों की संख्या बढ़कर 57 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इससे पहले नाबार्ड ने 2016-17 में इस तरह का सर्वे किया था जिसमें कृषि पर निर्भर ग्रामीण परिवारों की आबादी 48 प्रतिशत थी। उस समय 5000 रुपये से अधिक मासिक कृषि आय वाले परिवारों पर सर्वे किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों के परिवारों के लिए खेती सबसे बड़ा आय का स्रोत है, जो कुल मासिक आय का लगभग एक तिहाई (33 प्रतिशत) है। इसके बाद सरकारी या निजी सेवाओं का 23 प्रतिशत, मजदूरी का 16 फीसदी और अन्य उद्यमों का 15 फीसदी योगदान है। दूसरी ओर, गैर-कृषक परिवारों की आय में सरकारी या निजी नौकरियों का सबसे बड़ा हिस्सा 57 फीसदी है, जबकि मजदूरी से गैर-कृषक परिवारों को 26 फीसदी आय होती है। जिन परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उनकी औसत आय छोटी जोत वाले किसानों की तुलना में लगभग दोगुनी है। जिनके पास 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि है उनकी आय का अधिकांश हिस्सा नौकरी, मजदूरी या पशुपालन से आता है। इसमें सरकारी या निजी नौकरियों का 31 प्रतिशत, मजदूरी का 29 प्रतिशत और पशुपालन का योगदान 25 प्रतिशत है। छोटे किसानों की कुल आय में खेती का योगदान केवल 2 प्रतिशत है।

नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कृषक परिवारों की औसत मासिक आय गैर-कृषक परिवारों की औसत मासिक आय और सभी परिवारों की औसत मासिक आय से अधिक है। देश में सभी ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय 12,698 रुपये है, जबकि कृषक परिवारों की औसत मासिक आय 13,661 रुपये और गैर-कृषक परिवारों की औसत आय 11,438 रुपये है। 2016-17 के सर्वे में कृषक परिवारों की औसत मासिक आय 8,931 रुपये और गैर-कृषक परिवारों की 7,269 रुपये थी। सर्वे के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि 2016-17 से 2021-22 के बीच कृषि से आय अर्जित करने वाले परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही इन परिवारों की कृषि से होने वाली आय अन्य स्रोतों से होने वाली आय के मुकाबले बढ़ी है। ■

नाबार्ड सर्वे में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर ग्रामीण आबादी की संख्या 48 प्रतिशत से बढ़कर 57 फीसदी पर पहुंच गई है

मैन्यूफैक्चरिंग : नौ दिन चले अढ़ाई कोस

रोजगार बढ़ाने को जरूरी है जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग का अधिक योगदान

जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 25 फीसदी करने का लक्ष्य अधूरा

मोबाइल निर्माण, तैयार स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादों में मिली सफलता

युवा सहकार टीम

सरकार ने वर्ष 2014 में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को विकास का केंद्र मानते हुए वर्ष 2025 तक जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को तब के 15-16 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस उद्देश्य को पाने के लिए सरकार ने विशेष तौर पर मेक इन इंडिया अभियान भी चलाया। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उपायों में प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (पीएलआई) स्कीम भी विभिन्न उद्योग क्षेत्रों के लिए चलायी गईं। लेकिन इन सब उपायों का नतीजा सिफर ही रहा। आज भी देश की जीडीपी में उद्योगों की हिस्सेदारी 2014 के स्तर के आसपास ही घूम रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यह करीब 17 फीसद है। जबकि कई अर्थशास्त्रियों की राय में यह इससे कम भी हो सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक यह हिस्सेदारी 13 फीसद तक नीचे आ चुकी है।

बीते एक दशक में ऐसा क्या हुआ कि सरकार की कोशिशों के बावजूद देश में मैन्यूफैक्चरिंग के योगदान में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो सकी? हालांकि मेक इन इंडिया अभियान का एक दशक पूरा होने के बाद सरकार का दावा है कि कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। मसलन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो सरकार मानती है कि भारत

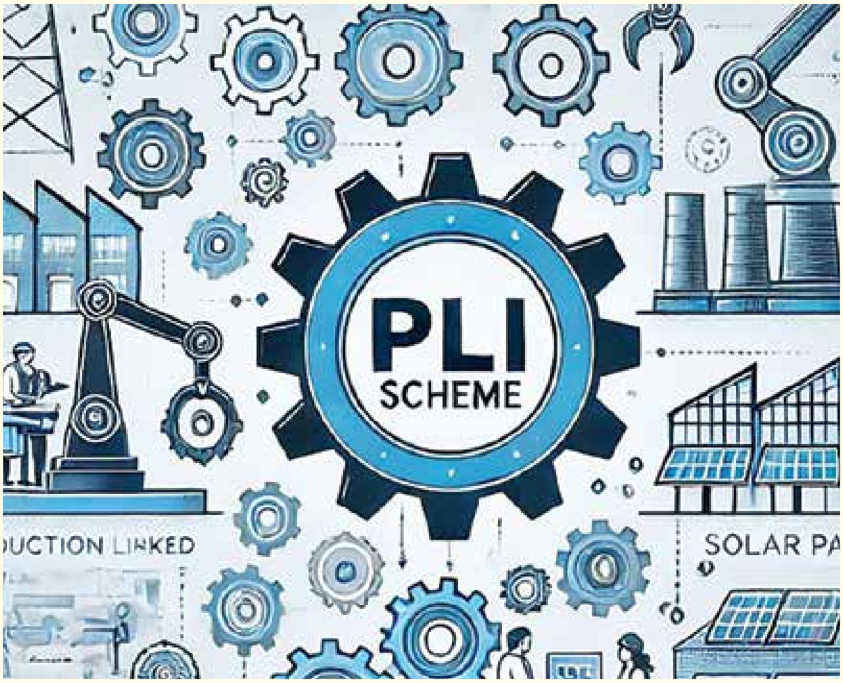

में इस्तेमाल होने वाले 99 फीसद मोबाइल का निर्माण भारत में हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अब तैयार स्टील उत्पादों का निर्यातक बन चुका है। यही नहीं रिन्यूबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसकी उत्पादन क्षमता में 400 गुणा इजाफा हुआ है।

सरकार ने मैन्यूफैक्चरिंग के विस्तार के लिए कई स्कीमों की घोषणा की। लेकिन पीएलआई जैसी स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग खासतौर पर मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग को हैंडसेट असेंबली में केंद्रित कर दिया। देश में बनने वाले स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 90 फीसद कलपुर्जों का आज भी आयात किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार अस्सी के दशक में ऑटो उद्योग को प्रोत्साहन देने के बाद कंपोनेंट इंडस्ट्री का विकास देश में बहुत तेजी से हुआ, वैसा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में नहीं हुआ। जबकि आज की तारीख में हम मोबाइल फोन निर्यात के मामले में भी अव्वल हैं। लगभग यही स्थिति रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर में भी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले पैनल व अन्य घरेलू उपकरण अत्यधिक लागत होने की वजह से आयात के मुकाबले महंगे पड़ते हैं। इसलिए बिजली उत्पादन में उतरने वाली अधिकांश कंपनियां आयातित उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को लेकर लचीला रुख अपनाने की वजह से इस क्षेत्र ने तेज विकास किया है।

यह सच है कि बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था में बहुत से बदलाव आये हैं और इसका आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2014 में देश का जीडीपी 2010 अरब डॉलर का था। इसमें 314 अरब डॉलर के निर्यात भी शामिल थे। उस वक्त जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15 फीसद थी। वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का आकार बढ़कर 3900 अरब डॉलर का हो गया है। निर्यात की हिस्सेदारी 437 अरब डॉलर की है। लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है। श्रीवास्तव के एक आलेख के मुताबिक, वर्ष 2014 में भी आज की तरह मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की देश के कारोबार में हिस्सेदारी 75 फीसद थी। लेकिन 2024 में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की तुलना में निर्यात की हिस्सेदारी 78.1 फीसदी से घटकर 64.6 फीसदी पर आ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल निर्यात में वृद्धि के बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों के निर्यात में बीते एक दशक में कमी आई है।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हमेशा से घरेलू और निर्यात बाजार उसकी वृद्धि की रफ्तार को तय करते आये हैं। वर्तमान में ये दोनों ही बाजार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं। सस्ते आयात की वजह से कई सेक्टर में घरेलू उत्पादों की मांग प्रभावित हो रही है। यही हाल निर्यात बाजार का भी है। अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनकी वजह से मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत उत्पादन की ऊंची लागत की है। चीन समेत कई दक्षिण एशियाई देश लागत के मामले में भारतीय उत्पादों को चुनौती दे रहे हैं। अगर हम औद्योगिक इस्तेमाल में आने

देश में बनने वाले स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाले 90 फीसद कलपुर्जों का आज भी आयात किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस प्रकार अस्सी के दशक में ऑटो उद्योग को प्रोत्साहन देने के बाद कंपोनेंट इंडस्ट्री का विकास देश में बहुत तेजी से हुआ, वैसा मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में नहीं हुआ।

बीते एक दशक में अर्थव्यवस्था का आकार भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में देश का जीडीपी 2010 अरब डॉलर का था। उस वक्त जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 15 फीसद थी। 2024 में जीडीपी का आकार बढ़कर 3900 अरब डॉलर का हो गया है लेकिन मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान वहीं का वहीं है।

वाली बिजली की लागत की बात करें तो चीन में प्रति किलोवाट इसकी लागत लगभग 0.06 से 0.08 डॉलर की आती है। जबकि भारत में यह 0.06 से 0.10 डॉलर की पड़ती है। यही नहीं उद्योगों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की दरों में भी काफी अंतर है। भारत में जहां ब्याज की दरें 9-10 फीसद तक चली जाती हैं तो चीन में यह 4-5 फीसद ही रहती है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों में तो सरकार निर्यात करने वाली मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों को अन्य प्रकार के प्रोत्साहन भी देती है। यही वजह है कि थाईलैंड, वियतनाम जैसे कई देशों को बीते कुछ वर्षों में दुनिया के बड़े मैन्यूफैक्चरों ने विस्तार के लिए चुना।

श्रम कानून भी उद्योगों के विस्तार में बड़ी अड़चन बने हैं। सरकार ने इस दिशा में कदम उठाये हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई तरह की कानूनी बाधाएं हैं जो कंपनियों में नई इकाइयां लगाने और पुरानी में क्षमता विस्तार के लिए हिचाकिचाहट पैदा करती है। भारत के मुकाबले चीन, वितयनाम और बांग्लादेश ने भारत के मुकाबले श्रम कानूनों को ज्यादा लचीला बनाया है। इसके अतिरिक्त नीति निरंतरता और दीर्घकालिक टैक्स नीति के अभाव ने भी मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को प्रभावित किया है। यही वजह रही है कि आजादी के बाद मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में योगदान कभी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ पाया। 1950 के दशक में यह अगर 8-9 फीसदी था तो 1980 के आसपास यह 14-16 फीसदी तक ही पहुंच पाया। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के वक्त यह माना गया था कि इससे अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी, किंतु ऐसा हो न सका। हालांकि 2000 के दशक में इसमें कुछ तेजी आई और यह लगभग 16-17 फीसदी तक जा पहुंचा। कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो मैन्यूफैक्चरिंग का योगदान 13-17 फीसद के बीच ही घूम रहा है।

मैन्यूफैक्चरिंग की रफ्तार को सरकार के कुछ अन्य फैसलों ने भी प्रभावित किया है। खासतौर पर अति लघु, लघु और मझौले उद्योग इन फैसलों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एमएसएमई के नाम से जाना जाने वाला यह सेक्टर रोजगार मुहैया कराने के मामले में काफी अहम है। लेकिन ऊंची ब्याज दरों, कोलेटरल की शर्त और पहले नोटबंदी और फिर जीएसटी ने इस क्षेत्र की कमर ही तोड़ दी। रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी। उसके बाद से यह क्षेत्र उबर नहीं पाया है। निर्यात में भी इस क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रभावित हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की मंदी और विदेशी उत्पादों की कम लागत ने इस क्षेत्र के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया है।

कई सेक्टरों में आयात शुल्क में कमी और द्विपक्षीय व मुक्त बहुपक्षीय कारोबारी समझौतों की वजह से देश में आयातित सामान की उपलब्धता आसान हो रही है। खासतौर पर महंगे उत्पादों के मामले में यह ट्रेंड अधिक देखने को मिला है। इन आयातित उत्पादों की मांग देश में तेजी से बढ़ी है जिनकी वजह से घरेलू उत्पादों की मांग कम हो रही है। कॉस्मेटिक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह ज्यादा अधिक स्पष्टता से दिख रहा है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू एफएमसीजी कंपनियों के कई उत्पादों को घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा में टिके रहना मुश्किल हो रहा है।

इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार (घरेलू व विदेश) दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। मैन्यूफैक्चरिंग की गुणवत्ता ही निर्यात को बढ़ाएगी और निर्यात बाजार में पैठ ही मैन्यूफैक्चरिंग को विस्तार का अवसर देगी। बीते एक दशक के अनुभव ने यह साबित किया है कि केवल प्रोत्साहन ही जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग के योगदान को बढ़ाने के लिए काफी नहीं हैं। उद्योगों के लिए ऐसी टिकाऊ टैक्स और प्रोत्साहन नीति का समन्वय करना होगा जो न केवल लागत कम करे बल्कि आयातित उत्पादों के साथ घरेलू उत्पादों को भी प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार हो। सरकार ने 2025 में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग के 25 फीसदी के योगदान के लक्ष्य को अब 2030 तक के लिए आगे बढ़ाया है। इस लक्ष्य को पाना है तो अगले छह वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ■

दुनिया सुनेगी भारतीय सहकारिता की गूंज

130 वर्ष में पहली बार नई दिल्ली में हो रहा सहकारिता का वैश्विक सम्मेलन

100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की प्रमुख थीम है 'सहकारिता-सबकी समृद्धि का द्वार'

युवा सहकार टीम

भारतीय सहकारिता आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ने लगी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए चुना गया है। सहकारिता आंदोलन के प्रमुख वैश्विक निकाय आईसीए के 130 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार हो रहा। सहकारिता के वैश्विक सम्मेलन में दुनिया के सौ से अधिक देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ कुल 3000 लोग हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में ही वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का बिगुल बजेगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महासभा की बैठक भी इसी दौरान होगी, जिसमें भारतीय सहकारिता की उपलब्धियों का डंका बजेगा।

भारत में सहकारिता की ताजा पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है। केंद्र सरकार ने सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए नए मंत्रालय का गठन किया और देश में थम सी गई सहकारिता को आगे बढ़ाने का दायित्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के हाथों में सौंपा। इसका नतीजा सबके सामने है। सहकारी क्षेत्र के संस्थानों के पुनर्गठन और निष्क्रिय हो चुकी प्राथमिक सोसायटियों में जान फूंक दी गई। मॉडल बायलॉज से प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) को ताकत दी गई और उसके कामकाज के दायरे को बढ़ाया गया। सहकारिता पर लागू टैक्स प्रणाली को तर्कसंगत बनाया गया। सहकारी चीनी उद्योग और टेक्स्टाइल से लेकर डेयरी और फिशरीज (दुग्ध और मत्स्य) क्षेत्र को सबल बनाया गया है।

भारतीय सहकारिता की मजबूत स्थिति को देखते हुए वैश्विक सहकारी आंदोलन के प्रमुख निकाय के रूप में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन 25-30 नवंबर तक भारत द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसकी मेजबानी की बागडोर विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको समेत देश की 17 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के हाथों में है। इन संस्थाओं में नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) भी शामिल है। इस वैश्विक सम्मेलन का थीम सब्जेक्ट ''सहकारिताएं- सबकी समृद्धि का द्वार' तय किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र के घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ होगा। सम्मेलन में भारतीय गांवों की थीम पर बने 'हाट' में भारतीय सहकारी उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।

आईसीए सम्मेलन में शामिल हो रहे प्रमुख व्यक्तियों में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को सहित संयुक्त राष्ट्र आर्थिक परिषद (यूएन ईसीओएसओसी) के अध्यक्ष, आईसीए के सदस्य और भारतीय सहकारी समितियों के प्रमुख भाग लेंगे। ■

स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल हो सहकारिता

फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसायटी कृभको के चेयरमैन **डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव** पहले भारतीय हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस-एशिया पेसिफिक के चेयरमैन चुने गए हैं। कृभको का चेयरमैन बनने से पहले वह नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के लंबे समय तक चेयरमैन रहे हैं। 19 मार्च, 1959 को जन्मे डॉ. यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य, झांसी निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। 25-30 नवंबर को भारत में पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) की महासभा और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह भारतीय सहकारिता आंदोलन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। सम्मेलन की तैयारियों और भारतीय सहकारिता क्षेत्र के भविष्य को लेकर **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने उनसे लंबी बातचीत की। पेश हैं उनके प्रमुख अंशः

इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस (आईसीए) की महासभा और कॉन्फ्रेंस भारत में पहली बार आयोजित हो रही है, इससे भारतीय सहकारिता आंदोलन को कितनी मजबूती मिलेगी?

आईसीए की महासभा पहली बार भारत में हो रही है। यह एक ऐतिहासिक समय है जब पूरी दुनिया की कोऑपरेटिव से जुड़े लोग हमारे देश में इकट्ठा होंगे। महासभा के साथ-साथ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है जिसमें पूरी दुनिया से जुड़े हुए सहकारी क्षेत्र के लोगों का विचार विमर्श होगा। पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव्स को एक दूसरे को सुनने का, जानने का, पहचानने का, कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा देश किस जगह खड़ा है, उनसे तुलना करने का एक जबरदस्त मौका मिला है। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, दूसरे लोगों से सीख कर हम उसे अपनाएंगे, हमलोग जो कर रहे हैं उसे दूसरे लोग अपनाएंगे। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव्स आकर अपना-अपना प्रेजेंटेशन देंगे। अभी हम 12-14 क्षेत्र में ही कोऑपरेटिव के माध्यम से काम कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि दुनिया में हर क्षेत्र में काम करने वाले कोऑपरेटिव्स हैं। हम चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का काम हो तो उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा क्योंकि कोऑपरेटिव की पहुंच आखिरी व्यक्ति तक है।

इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन से सहकारिता क्षेत्र को कारोबार बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी?

आईसीए की महासभा और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे देश के कोऑपरेटिव्स को बहुत अच्छा मौका मिला है अपने को बेहतर बनाने का। हम दूसरे लोगों से क्या-क्या ले सकते हैं, दूसरा, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव बिजनेस

करने और बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके लिए हम जगह-जगह मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। बहुत सारी वस्तुएं और उत्पाद हैं जिनका हम कोऑपरेटिव के माध्यम से निर्यात और आयात कर सकते हैं। यह कोऑपरेटिव के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सरकार ने निर्यात के लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) का गठन किया है। इसके माध्यम से जिस भी कृषि उत्पाद का निर्यात किया जाता है उसकी खरीद सीधे कोऑपरेटिव से ही होती है। इसका लाभ यह है कि उत्पादकों को अच्छी कीमत मिलती है और जो मुनाफा होता है वह व्यापारियों और बिचौलियों की बजाय सीधे उत्पादकों तक पहुंचता है।

आप आईसीए-एशिया पैसिफिक के पहले भारतीय अध्यक्ष हैं। सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है?

सहकारिता क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाया जा रहा है। महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता है उसके लिए भी काम करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोऑपरेटिव बनाकर उन्हें शिक्षित किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस और लेक्चर आयोजित कर उन्हें कोऑपरेटिव से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमने सरकार को भी सुझाव दिया है कि कोऑपरेटिव का एक चैप्टर स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए ताकि सहकारिता की बुनियादी बातों से बच्चों को अवगत कराया जा सके। इसे एग्रीकल्चर वाले पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है ताकि उन्हें इसका बुनियाद ज्ञान हो सके। इससे उनमें सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इसका ज्ञान पढ़ाई के दौरान ही हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। जो युवा रोजगार के लिए भटकते हैं वे कोऑपरेटिव बनाकर काम करें तो न सिर्फ अपना, बल्कि अन्य लोगों का भी जीवन बेहतर बना सकते हैं। कोऑपरेटिव में रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने की असीमित क्षमता है जिसका फायदा युवा उठा सकते हैं।

अलग मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता के क्षेत्र में क्या नया बदलाव आया है?

जब से अलग मंत्रालय बना है तब से इस क्षेत्र में काफी बदलाव हुए हैं। खासकर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसायटी जिसे पैक्स कहा जाता है, की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्हें नए-नए क्षेत्र में कारोबार करने की मंजूरी मिली है। पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कर उन्हें सीधा राज्य और केंद्र से जोड़ दिया गया है। जो पैक्स ठप पड़े हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है और जिन पंचायतों में पैक्स नहीं हैं वहां इसका गठन किया जा रहा है। अगले पांच साल में डेयरी, मत्स्य सहित दो लाख नई सहकारी समितियों का गठन करने का लक्ष्य तय किया गया है। पैक्स को लगभग 35-40 तरीके के बिजनेस करने का मौका सरकार ने दिया है। इससे उन कोऑपरेटिव सोसायटीज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जरूरत की चीजें पैक्स के माध्यम से सही कीमत पर और आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, गांव के लोग अपने उत्पाद कोऑपरेटिव को बेच सकेंगे और उन्हें गांव के लोग खरीद सकेंगे। उन्हें बाजार जाने की आवश्कता नहीं पड़ेगी और गांव का पैसा गांव में ही रहेगा, बल्कि बाहर का पैसा भी गांव में आएगा। इससे गांव का विकास निश्चित है क्योंकि खरीद-बिक्री से जो लाभ होगा उसे सहकारी समिति के सदस्यों में ही वितरित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि सहकारिता क्षेत्र अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होता जा रहा है।

आप फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसायटी कृभको के अध्यक्ष भी हैं। कृभको की क्या स्थिति है?

आज की तारीख में कृभको अच्छी स्थिति में है। पहले हम सालाना 15 लाख टन यूरिया का उत्पादन करते थे। अब सालाना 50-60 लाख टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन कर रहे हैं। हमने दो सब्सिडियरी बनाई है। एक प्रोसेसिंग के लिए और एक निर्यात के लिए। प्रोसेसिंग सब्सिडियरी के तहत एक एथेनॉल प्लांट लगाया है। इसका फायदा मक्का किसानों को मिल रहा है और उन्हें उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल रही है। इसी तरह, कृषि उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं। ■

पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव्स को एक दूसरे को सुनने का, जानने का, पहचानने का, कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा देश किस जगह खड़ा है, उनसे तुलना करने का एक जबरदस्त मौका मिला है। हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, दूसरे लोगों से सीख कर हम उसे अपनाएंगे, हमलोग जो कर रहे हैं उसे दूसरे लोग अपनाएंगे। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया के कोऑपरेटिव्स आकर अपना-अपना प्रेजेंटेशन देंगे।

विश्व की कौशल राजधानी बनेगा भारत

वैश्विक समुदाय भारत को दुनिया भर में शिक्षा, कौशल, हेल्थकेयर और सॉफ्टवेयर विकास में व्यापक अवसरों के साथ मानव संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है। भारत के युवाओं को इन अवसरों के लिए तैयार करने के लिए सरकार उनके कौशल को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ रही है।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

युवा सहकार टीम

राष्ट्रीय और वैश्विक अवसरों के लिए भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स (आईआईएस) की शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग सहित कई ट्रेडों में अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस इंडस्ट्री 4.0 के लिए एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करना है। यह सर्विस और मैन्यूफैक्चरिंग दोनों सेक्टर्स के साथ-साथ अन्य उभरते बिजनेस को भी आगे बढ़ाएगा। कौशल विकास के इस संस्थान से हर साल 5,000 विद्यार्थी प्रशिक्षित होकर निकलेंगे जो भारत की आर्थिक तरक्की में मददगार होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इस संस्थान का उद्घाटन किया।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और टाटा आईआईएस (टाटा ट्रस्ट की कंपनी) के सहयोग से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'दुनिया किसी देश पर तभी भरोसा करती है जब उसके युवा आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आज भारत के युवाओं का आत्मविश्वास देश के लिए एक नए भविष्य की कहानी लिख रहा है। वैश्विक समुदाय भारत को दुनिया भर में शिक्षा, कौशल, हेल्थकेयर और सॉफ्टवेयर विकास में व्यापक अवसरों के साथ मानव संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है। भारत के युवाओं को इन अवसरों के लिए तैयार करने के लिए सरकार उनके कौशल को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ रही है।'

मुंबई के चूनाभट्टी स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (एनएसटीआई) के भीतर चार एकड़ के विशाल कैम्पस में निर्मित आईआईएस को अत्याधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से लैस इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। आईआईएस मुंबई फैक्टरी ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, मेक्ट्रोनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह संस्थान शुरूआत में छह विशेष पाठ्यक्रम जैसे एडवांस्ड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन

एंड रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फंडामेंटल्स, एडवांस्ड एआरसी वेल्डिंग तकनीक, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्पेशलिस्ट और टू और थ्री व्हीलर ईवी तकनीशियन लॉन्च करेगा। संस्थान निकट भविष्य में उम्मीदवारों के सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए छात्रावास सुविधाओं का भी विस्तार करेगा।

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयन्त चौधरी ने कहा, 'आईआईएस जैसे संस्थान फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को वास्तविकता में बदलेंगे। हमारे युवाओं को अत्याधुनिक विशेषज्ञता से लैस करके यह संस्थान न केवल भारत के भीतर अवसरों के द्वार खोलेगा, बल्कि उन्हें वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी तैयार करेगा।'

चौधरी के मुताबिक, 'अपने युवाओं को एडवांस तकनीकी कौशल और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके हम भारत को वैश्विक कौशल विकास में सबसे आगे ला रहे हैं। यह पहल प्रशिक्षण देने से कहीं अधिक है। इसका उद्देश्य देशभर में युवा प्रतिभाओं के लिए न केवल उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए मार्ग तैयार करना है, बल्कि भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बनना भी है। हम अत्याधुनिक उद्योगों के साथ इस तरह की रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी स्किलिंग फ्रेमवर्क न केवल प्रासंगिक हों, बल्कि दूरदर्शी भी हों। एक गतिशील, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाना जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की तेजी से विकसित हो रही मांगों को पूरा करने में सक्षम हो।'

संस्थान में शुरू में 15 से अधिक वैश्विक और इंडियन ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर (ओईएम) के साथ साझेदारी में विकसित एडवांस्ड लैब होंगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को वास्तविक इंडस्ट्री इक्विपमेंट का उपयोग करके सस्ती कीमत पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। एक बार जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, तो वे ईवी मैन्युफैक्चरर, एआई और रोबोटिक्स जैसे नए युग के उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

अपनी मुख्य पेशकशों के अलावा आईआईएस उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि फेनुक इंडिया के साथ इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स, एसएमसी इंडिया के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और ताज स्काईलाइन के साथ कुलिनरी और कोर हाउस कीपिंग प्रदान करेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण और मजबूत उद्योग संबंधों के लिए अपने इनोवेटिव अप्रोच के साथ आईआईएस भारत में कौशल विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।

महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उद्घाटन के मौके पर कहा, 'अत्याधुनिक सुविधा से लैस आईआईएस विश्व भर के लोगों को आकर्षित करेगा। टाटा समूह विश्वास और विकास का पर्याय है। यह इस संगठन से जुड़े हर उम्मीदवार के लिए काम करने और सीखने का अवसर है।'

आईआईएस के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने कहा, 'भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में कुशल, रेजिलेंस वर्कफोर्स की मांग लगातार बढ़ रही है जो बदले में उत्पादकता, आर्थिक विकास, समृद्धि और राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ा सकता है। अपने युवाओं को उपयोगी कौशल से लैस करके हम उन्हें स्वावलंबन और सम्मान का जीवन जीने के लिए सशक्त बना सकते हैं और उद्योग की उभरती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ देश की चुनौतियों को हल करने और युवाओं को रोजगार और उद्यम की ओर ले जाने में मदद करने के लिए साहसिक और त्वरित कदम उठाने के टाटा समूह के विजन का प्रतीक है।' ■

'आईआईएस' जैसे संस्थान फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भारत को 'विश्व की कौशल राजधानी' बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को वास्तविकता में बदलेंगे।

श्री जयंत चौधरी
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्वेत क्रांति 2.0 से डेयरी क्षेत्र का होगा कायाकल्प

60 सालों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) ने किसानों और महिलाओं को सशक्त एवं संगठित किया

कोऑपरेटिव उत्पादों की ब्रांडिग कर उन्हें कॉरपोरेट उत्पादों के साथ स्पर्धा के लिए तैयार करना ही हमारी सफलता है- श्री अमित शाह

सब्जियों की प्रोसेसिंग से भारतीय किसानों की सब्जियां पूरी दुनिया में जाएंगी और मुनाफा सीधे किसानों को मिलेगा

उत्तराखंड के बद्री गाय घी और गुजरात के गिर गाय घी ब्रांड की हुई लांचिंग

युवा सहकार टीम

सहकारिता के माध्यम से गांवों की महिलाओं एवं किसानों की आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करके सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। इसी दिशा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए गुजरात के आणंद में 300 करोड़ रुपये की लागत से अनेक किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के हीरक जयंती (60वीं वर्षगांठ) एवं श्री त्रिभुवन पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारिता क्षेत्र में कई पहल की गई हैं। इससे भारत में सहकारिता आंदोलन मजबूत हो रहा है।

सहकारिता क्षेत्र में लगभग 22 राज्य संघ और 231 जिला संघ बने हैं। 28 विपणन डेयरी और 21 दुग्ध उत्पादक कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें किसानों के हितकारी सभी प्रमुख पहल शामिल की गई हैं। इसका मकसद दुग्ध क्षेत्र का विस्तार कर निर्यात को बढ़ावा देना है। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में नंबर एक तो बन गया है लेकिन निर्यात के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है। भारत में जितना दूध उत्पादन होता है उसका ज्यादातर हिस्सा यहीं खप जाता है। अमित शाह ने कहा कि श्वेत क्रांति 2.0 के तहत सरकार एक लाख नई और मौजूदा डेयरियों को सशक्त करेगी। इससे दुग्ध क्षेत्र का विस्तार होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत ने 231 लाख टन दुग्ध उत्पादन के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और हम विश्व में पहले स्थान पर है। हमारी दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 6 फीसदी है जबकि वैश्विक दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर 2 फीसदी है। आज देश में आठ करोड़ ग्रामीण परिवार रोज दुग्ध उत्पादन करते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ डेढ़ करोड़ ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हैं। श्री शाह ने कहा कि इस बात का सीधा अर्थ है कि बाकी 6.5 करोड़ परिवारों को उचित दाम नहीं मिल रहा है और उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का संकल्प है कि आने वाले समय में दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए सभी आठ करोड़ किसान

पूरी दुनिया में पहुंचेंगी भारतीय सब्जियां

दूध के बाद अब नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने सब्जियों की प्रोसेसिंग शुरू की है जिससे भारत के किसानों की सब्जियां पूरी दुनिया में जाएंगी और उनका मुनाफा कोऑपरेटिव मॉडल के तहत नीचे तक पहुंचेगा। एनडीडीबी ने 10,000 किसान उत्पाद संगठन (एफपीओ) भी पंजीकृत किए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने 210 करोड़ रुपये की लागत से मदर डेयरी के फल और सब्जी प्रसंस्करण इकाई का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उत्तराखंड के बद्री घी और मदर डेयरी के गिर घी ब्रांड की भी शुरूआत की। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव के उत्पाद की ब्रांडिग व मार्केटिंग करके उसे बाजार में कॉरपोरेट के साथ स्पर्धा के लिए तैयार करना ही सहकारिता की सफलता है। आज सहकारी अमूल ब्रांड पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के एप्रीकॉट, हिमाचल के सेब और मेघालय के अन्नानास के किसानों को भी नई योजनाओं से फायदा मिलेगा।

परिवारों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा मिले और वे सभी सहकारिता क्षेत्र से जुड़ सकें। एनडीडीबी की पहल के बाद अब पूरे डेयरी क्षेत्र के सभी संयंत्र भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे।

एनडीडीबी ने सहकारिता की नींव मजबूत की

श्री शाह ने कहा कि 60 साल में एनडीडीबी ने देशभर में सहकारिता के साथ किसानों और महिलाओं को न केवल सशक्त और संगठित किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागृत भी किया। एनडीडीबी ने ग्रामीण क्षेत्र और देश के विकास को गति देने के साथ-साथ कृषि को अत्मनिर्भर भी बनाया। त्रिभुवन दास पटेल ने गरीब किसानों के सशक्तिकरण के लिए छोटी सी सहकारी समिति के रूप में एनडीडीबी की नींव रखी थी जो आज देश ही नहीं, बल्कि विश्व का बहुत बड़ा संस्थान बन गई है और दो करोड़ किसानों को साथ लेकर हजारों करोड़ रुपये का व्यापार कर रही है। एनडीडीबी के प्रयासों से 2023 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 167 किलोग्राम सालाना हो गई है, जबकि विश्व में दूध की औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता 117 किलोग्राम ही है।

श्री शाह ने कहा कि 100 रुपए की शेयर पूंजी से पूंजी निर्माण कर अमूल आज 60 हजार करोड़ का सालाना व्यापार कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि 1964 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अमूल डेयरी को देखने गए, उन्होंने तभी तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि पूरे देश के पशुपालक किसानों को इस सफल प्रयोग का फायदा मिलना चाहिए। इसके बाद ही शास्त्री जी ने एनडीडीबी की स्थापना का निर्णय लिया।

एनडीडीबी की तरल दूध की बिक्री 427 लाख लीटर और खरीद 589 लाख लीटर प्रति दिन है और इसका राजस्व 344 करोड़ रुपए से बढ़कर 426 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें शुद्ध मुनाफा 50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जब पशुपालन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है तो इससे किसानों की समृद्धि के साथ ही देश के कुपोषित बच्चों को भी पोषण मिलता है। अमूल के जरिये जो विश्वास खड़ा हुआ है, उसने न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण किया, बल्कि बच्चों को पोषण देकर उन्हें सशक्त नागरिक बनाने में योगदान दिया। ■

60 साल में एनडीडीबी ने देशभर में सहकारिता के साथ किसानों और महिलाओं को न केवल सशक्त और संगठित किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागृत भी किया। एनडीडीबी ने ग्रामीण क्षेत्र और देश के विकास को गति देने के साथ-साथ कृषि को अत्मनिर्भर भी बनाया।

सहकारिता की चुनौतियां और भविष्य

निशि भट्ट

> **देशभर में सहकारी समितियों का विकास कुछ ही राज्यों तक सीमित है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में ही सहकारी समितियों की अधिकता है, जबकि देश के अन्य प्रदेश सहकारी आंदोलन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसलिए देश के सहकारी आंदोलन को असंतुलित आंदोलन कहा जाता है।**

भारत में सहकारिता की शुरूआत होने से पहले इंग्लैंड में सहकारिता को पूंजीवाद और समाजवाद के बीच के रास्ते के रूप में अपनाया जा चुका था। वैश्विक स्तर पर सहकारिता की उपलब्धियों से प्रभावित होकर 20वीं सदी की शुरूआत में इसे भारत में अपनाने के प्रयास शुरू हुए। इसी क्रम में वर्ष 1904 में सहकारी साख अधिनियम पारित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप देशभर में सहकारी साख समितियों का गठन किया गया, लेकिन कुछ समय बाद महसूस किया गया कि मात्र ऋण या साख सुविधाओं से देश के किसानों और कारीगरों के जीवन को नहीं सुधारा जा सकता है। इसी क्रम में वर्ष 1912 में सहकारी समिति विधान पास किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास चलता रहा।

वर्ष 2021 में देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसके बाद सहकारिता के लगभग सभी क्षेत्रों के लिए योजनाओं को लागू किया गया। कृषि क्षेत्र में पैक्स को मजबूत किया गया, उर्वरक सहकारी समितियां, जैसे इफको के नवाचारों से देश की सहकारिता को विश्व स्तर पर पहचान मिली। सहकारिता मॉडल में तमाम सुधारों के बावजूद सहकारिता से होने वाले आर्थिक एवं गैर आर्थिक लाभ आशा अनुकूल नहीं रहे हैं। इसके प्रमुख कारण हैं–

सरकारी दखल अधिक होना– देश में सहकारिता आंदोलन को जनता द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। अधिकांश फैसलों के लिए सहकारी समितियों के सदस्य सरकार द्वारा बनाए गए सख्त नियमों से बंधे होते हैं क्योंकि सहकारी समितियां सरकारी सहायता पर निर्भर रहती हैं, इसलिए वे स्वावलंबी नहीं हो पा रही हैं।

साख समितियों की अधिकता– सहकारी समितियों के व्यापक दायरे की बात करें तो इसमें भी सहकारी साख समितियों की अधिकता है। इससे सहकारी आंदोलन की परिधि में वे व्यक्ति भी आ जाते हैं, जिन्हें साख या ऋण की आवश्यकता ही नहीं होती है। समितियों के संचालन में कुछ प्रमुख लोगों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वे सरकारी

वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और जरूरतमंद लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है।

फर्जी सहकारी समितियों की स्थापना– सहकारी समितियों पर क्योंकि गांव के संपन्न लोगों का हस्तक्षेप अधिक होता है, इसलिए वह आयकर अथवा सीलिंग कानूनों से बचने के लिए फर्जी सहकारी समितियों की स्थापना आसानी से कर लेते हैं। लंबे समय तक सहकारी समितियों में ऐसी परंपरा देखी गई कि अपने ही परिवार के सदस्यों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिससे समितियों का कारोबार लंबे समय तक परिवार के सदस्यों के बीच ही होता रहा। इससे जरूरतमंद ग्रामीण लोगों को समितियों के गठन का लाभ नहीं मिला।

अकुशल प्रबंधन– भारत की सहकारी समितियो में अभी कुशल और व्यवसायिक व्यक्तियों की कमी है। भारत में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अपने राजनीतिक हित होते हैं। वह समितियों के माध्यम से अपने राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाने की मंशा से समितियों के साथ जुड़ते हैं। ऐसे में समितियों का विकास प्राथमिकता नहीं रह जाता।

क्षेत्रीय असमानता– देशभर में सहकारी समितियों का विकास कुछ ही राज्यों तक सीमित है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में ही सहकारी समितियों की अधिकता है, जबकि देश के अन्य प्रदेश सहकारी आंदोलन की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसलिए देश के सहकारी आंदोलन को असंतुलित आंदोलन कहा जाता है। हालांकि, यह भी सही है कि राज्य सरकारों द्वारा सहकारी समितियों के सम्यक विकास के लिए अधिक प्रयास भी नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त तमाम चुनौतियों के बावजूद समाज के निर्धन और अभावग्रस्त व्यक्तियों के आर्थिक उद्धार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सहकारी आंदोलन को सफल बनाना जरूरी है। इसके लिए कुछ सुझावों को अपनाया जा सकता है–

युवओं को प्रतिनिधित्व– सहकारी समितियों में पारंपरिक व्यवस्था से अलग शिक्षित युवाओं को अधिक से अधिक शामिल करना होगा। युवाओं की सहभागिता से सहकारी समितियों को अधिक व्यावसायिक तरीके से संचालित किया जा सकेगा। केवल सदस्यों तक ही युवाओं का दखल न हो, बल्कि उन्हें लीडरशिप की भूमिका में शामिल किया जाए। समितियों का चुनाव पारदर्शी ढंग से कराया जाना चाहिए, जिससे समितियों में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप कम किया जा सके। हालांकि नई सहकारी नीति में इन सभी पहलूओं को शामिल किया गया है जिससे भविष्य में सहकारी समितियों का संचालन अधिक बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

ऋण स्वीकृति से पहले जांच– सहकारी साख समितियों द्वारा दिए गए ऋण अधिकतर अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इससे ऋण की वापसी मुश्किल होती है। इसलिए जरूरी है कि ऋण देने से पहले समितियों की पड़ताल सही तरीके से कर ली जाए। इसके लिए साख समितियों में निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार– सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जिन देशों ने प्रमुखता से ध्यान दिया, वहां इस आंदोलन का तेजी से विस्तार हुआ। भारत में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस संदर्भ में प्रयास काफी तेज किए गए हैं। देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय का काम भी शुरू कर दिया गया है, वहीं कई प्रमुख राज्यों में सहकारिता प्रबंधन संस्थान सहकारिता शिक्षा और व्यवस्था की शिक्षा भी दे रहे हैं।

सहकारिता के नवाचारों से विकास और रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं, युवाओ का भी इस ओर रुझान बढ़ रहा है। सहकारिता को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और उद्यम के विकल्प देने का सबसे बेहतर माध्यम माना गया है। सुधारों का क्रम जारी है, सही व्यवस्था और संचालन से सहकारिता भारत को विकसित बनाने में अपनी सहभागिता मजबूत करेगी। ■

सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर जिन देशों ने प्रमुखता से ध्यान दिया, वहां इस आंदोलन का तेजी से विस्तार हुआ। इंग्लैंड, स्वीडन, डेनमार्क आदि देशों में सहकारी प्रशिक्षण और शिक्षा का एक मजबूत तंत्र काम करता है। हालांकि, भारत में नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस संदर्भ में प्रयास काफी तेज किए गए हैं।

सहकारिता के प्रयोग से झारखंड में बदला जीवन

युवा सहकार टीम

सहकारिता के जरिए जीवन में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं, झारखंड के सहकारी संगठन इसका सजीव उदाहरण हैं। आदिवासी इलाकों से लेकर किसानों और महिलाओं के लिए ये संगठन निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे कई सहकारी संगठन हैं जिनकी मदद से ग्रामीण और आदिवासी जनता की न केवल आमदनी बढ़ी है बल्कि उनके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। राज्य में कृषि, पशुपालन और वन उपज पर ध्यान केंद्रित करने वाले कई संगठन राज्य में सहकारी आंदोलन की नींव रहे हैं।

राज्य के प्रमुख सहकारी संगठनों में वेजफेड भी शामिल है जो सब्जी प्रसंस्करण और विपणन पर आधारित है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लाख मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड (जेएचएएससीओएलएएमपीएफ), यह सहकारी संगठन लाख का विपणन करती है। इसी तरह झारखंड स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग लिमिटेड (जेएचएएमएफसीओएफईडी) लघु वन उपज और लघु वन उपज का प्रबंधन करता है। झारखंड के एक अन्य अतिरिक्त सफल सहकार में झारखंड राज्य कोऑपरेटिव ऑफ फिश (जेएचएएससीएफआईएसएच) है, जो मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है। सिद्धो कान्हो कृषि और वन उपज सहकारी संघ मुख्य रूप से कृषि और वन उत्पादों के उत्पादन का कार्य करती है। झारखंड में 2028 लार्ज एरिया मल्टीपरपज सोसाइटीज (लैम्प्स) और 2374 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसायटी (पैक्स) हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 9000 अन्य सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं।

झारखंड सहकारिता विभाग किसानों को सहायता देने और राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रमों को लागू करती है। इनमें झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रमुख है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली क्षति का सामना करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

झारखंड सहकारिता विभाग किसानों को सहायता देने और राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रमों को लागू करती है। इनमें झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रमुख है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को होने वाली क्षति का सामना करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना समय पर ऋण न चुका पाने वाले किसानों को ब्याज में छूट प्रदान करती है। धान खरीद योजना के तहत लैम्प्स के माध्यम

लाख उद्योग के लिए समर्पित सहकार

झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन और खरीद महासंघ लिमिटेड एक सहकारी संगठन है जो लंबे समय से लाख उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 1963 में स्थापित यह महासंघ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए भी प्रतिबद्ध है और लाभ से अधिक सेवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। महासंघ की स्थापना लाख उत्पादन के काम में जुड़े उत्पादकों के शोषण को दूर करने और उन्हें स्टिकलॉक के उचित मूल्य प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जिससे लाख उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिले। महासंघ झारखंड में लाख से संबंधित उत्पादों के लिए सबसे बड़े चैनलों में से एक है और लाख की खेती में लगे आदिवासी आबादी के आर्थिक हितों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

से धान किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी सुनिशिचत करती है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण प्रणाली प्रकिया को अपनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिताओं के बुनियादी ढांचा विकास और कम्प्यूटरीकरण का काम लैम्पस या फिर पैक्स की सहायता से किया जाता है। कौशल विकास और प्रशिक्षण में झारखंड की सहकारी समितियां पीछे नहीं हैं। सहकारी समितियों और कृषि चौपालों के माध्यम से कृषि संबद्ध गतिविधियों और हस्तशिल्प जैसे विभिन्न चीजों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी तरह कार्यशील पूंजी सहायता किसानों के लिए उर्वरक, बीज और कीटनाशको जैसे कृषि इनपुट की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लैम्प्स और पैक्स को धन का आवंटन किया जाता है। यह सभी योजनाएं किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और झारखंड में एक मजबूत सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

गतिविधियां और उपलब्धियां

सहकारी समितियां, राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लैम्प्स तथा पैक्स को कम ब्याज दरों पर लघु एवं मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करती हैं, जिससे छोटे व मझोले किसानों के लिए ऋण की सुलभता हो जाती है। राज्य सहकारी बैंकों में वर्ष 2021-22 में 2033.76 करोड़ रुपये जमा किए गए और किसान क्रेडिट कार्ड में 12.01 करोड़ रुपये ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए। लैम्प्स और पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी काम करते हैं, जिनमें से 934 सीएससी कंप्यूरीकृत और 573 प्रज्ञा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में कुल 1,408,289 किसानों ने पंजीकरण कराया। अहम यह है कि यह सहकारी समितियां बीज और उर्वरक खरीद के लिए 21 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी प्रदान करती है और 1,339 लैम्प्स और पैक्स की सहायता से 1.46 लाख टन भंडारण सुविधा देती हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में वे बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे कृषि उपकरणों और इनपुट सेवाएं प्रदान करते हैं।

भंडारण और संरक्षण को बढ़ाने के लिए झारखंड ने 19 कोल्ड स्टोरेज जिनकी क्षमता 5000 टन है, 139 कोल्ड रूम और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 32 सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित करने की वजह से लघु वनोपज की खरीद से हजारों आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचता है। 12 राज्य स्तरीय सहकारी लघु वनोपज, सब्जियां, मत्स्य पालन, लाख उत्पादन और डेयरी क्षेत्र संचालित करती हैं। इसी तरह झारखंड दुग्ध महासंघ (जेएमएफ) मेधा छह दूध प्रसंस्करण इकाइयों का संचालन करता है और 18 जिलों में गुणवत्ता परक दूध की आपूर्ति करता है। झारखंड स्टेट माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग लिमिटेड से सीधे रूप से 25,000 से अधिक आदिवासी परिवारों की आजीविका जुड़ी है। मॉडल दुकानों के माध्यम से इमली, चिरौंजी और बीजू आम जैसे उत्पादों का विपणन किया जाता है। वहीं कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बुनियादी ढांचे को बेहतर कर इस व्यापार

भंडारण और संरक्षण को बढ़ाने के लिए झारखंड ने 19 कोल्ड स्टोरेज जिनकी क्षमता 5000 टन है, 139 कोल्ड रूम और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 32 सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड रूम स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित करने की वजह से लघु वनोपज की खरीद से हजारों आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचता है।

को बढ़ावा देता है। वर्ष 2007 में स्थापित झारखंड राज्य लघु वनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लिमिटेड महासंघ से 197 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां लैम्प्स, पैक्स, विशेष समितियां और 50 से अधिक स्वयं सहायता समूह इसके सदस्य है और यह अपनी योजनाओं के माध्यम से लगभग 25,000 आदिवासी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। लाख और तेंदू पत्ता को छोड़कर झामफकोफेड को राज्य के सभी माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस (एमएफपी) पर काम करने का अधिकार है जैसे इमली, चिरौंजी, महुआ, करंज, कुसुम, शहद, साल आदि। झामफकोफेड राज्य में संबद्ध सभी सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों से एमएफपी की खरीद करता है और उत्पादों का मूल्यवर्धन करता है।

झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी सब्जी विपणन संघ लिमिटेड वेजफेड झारखंड में सब्जी उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्पित शीर्ष सहकारी समिति है। महासंघ का उद्देश्य उत्पादकों को सहकारी संरचनाओं में संगठित करके एक अधिक कुशल और टिकाऊ सब्जी मूल्य श्रृंखला बनाना है।

सहकार में महिलाओं की भागीदारी भी मजबूत

झारखंड की सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी है। झारखंड महिला स्वावलंबी पोल्ट्री सहायक संघ लिमिटेड एक सहकारी संगठन है जो झारखंड में ग्रामीण महिलाओं को मुर्गी पालन के माध्यम से सशक्त बनाने का काम करती है। सहकारी संघ का लक्ष्य वैकल्पिक आजीविका के ऐसे अवसरों को प्रदान करना है जो भूमि पर कम निर्भर हो और कृषि आय के पूरक बन सकें। संघ का एक मिशन ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना भी है, जो नए उत्पादों की बढ़ती मांग को विशेष रूप से शहर वेजफेड से सब्जी उत्पादकों को मिला लाभ।

झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी सब्जी विपणन संघ लिमिटेड वेजफेड झारखंड में सब्जी उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए समर्पित शीर्ष सहकारी समिति है। महासंघ का उद्देश्य उत्पादकों को सहकारी संरचनाओं में संगठित करके एक अधिक कुशल और टिकाऊ सब्जी मूल्य श्रंखला बनाना है। वेजफेड का मिशन सब्जी उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां उपलब्ध कराना है। वेजफ्रेश सहकारी समिति का ही एक प्रयास है, जो एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है। सहकारी समिति के माध्यम से दो स्तरीय संरचना में सब्जियों का वितरण किया जाता है जिसमें जमीनी स्तर पर प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति और राज्य स्तर पर एक शीर्ष सब्जी सहकारी समिति शामिल होती है। यह संरचना झारखंड में उत्पादित कुल सब्जियों के कुशल विपणन और वितरण की सुविधा प्रदान करती है। यह संगठन छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए आजीविका का एक स्थायी साधन प्रदान करती है, जो अकसर बेहद गरीब परिवारों से आती हैं। सामूहिक विपणन, ब्रांडिंग और खुदरा बिक्री जैसी पहलों के माध्यम से महासंघ का लक्ष्य उत्पादन लागत को कम करना, गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना और अपने सहकारी सदस्य समितियों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए एक मजबूत बाजार पहुंच को स्थापित करना है। ■

दोगुने मुद्रा लोन से बढ़ेगा स्वरोजगार

वित्त वर्ष 2015-16 से 18 अक्टूबर, 2024 तक 50,13,86,332 आवेदन को मिली मंजूरी

इस समय तक कुल 31,09,956.07 करोड़ रुपये के मुद्रा लोन की दी गई स्वीकृति

अब तक 30,36,534.06 करोड़ रुपये के लोन का किया गया डिस्बर्समेंट

युवा सहकार टीम

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण केटेगरी में दस लाख रुपये से अधिक की राशि का कर्ज लेने के इच्छुक उद्यमियों का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की इस वर्ष के बजट में की गई इस घोषणा से संबंधित अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में तरुण कैटेगरी के मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई थी। इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने तरुण कैटेगरी के तहत लिए गए 10 लाख रुपये तक के लोन का भुगतान कर दिया है। अब वे 20 लाख रुपये तक लोन ले सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, नई कैटगरी को तरुण प्लस नाम दिया गया है। बिना गारंटी के मिलने वाली कर्ज की राशि को बढ़ाए जाने से युवा न सिर्फ स्वरोजगार के लिए और अधिक प्रेरित होंगे, बल्कि इससे रोजगार के नए-नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्वरोजगार को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में रहा है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में रोजगार के लिए सिर्फ नौकरियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। स्वरोजगार को बढ़ावा देकर न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से उन्नत किया जा सकता है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत स्वरोजगार करने वाले युवाओं और पहले से अपना कारोबार करने वाले छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता था। मोदी सरकार ने अपने

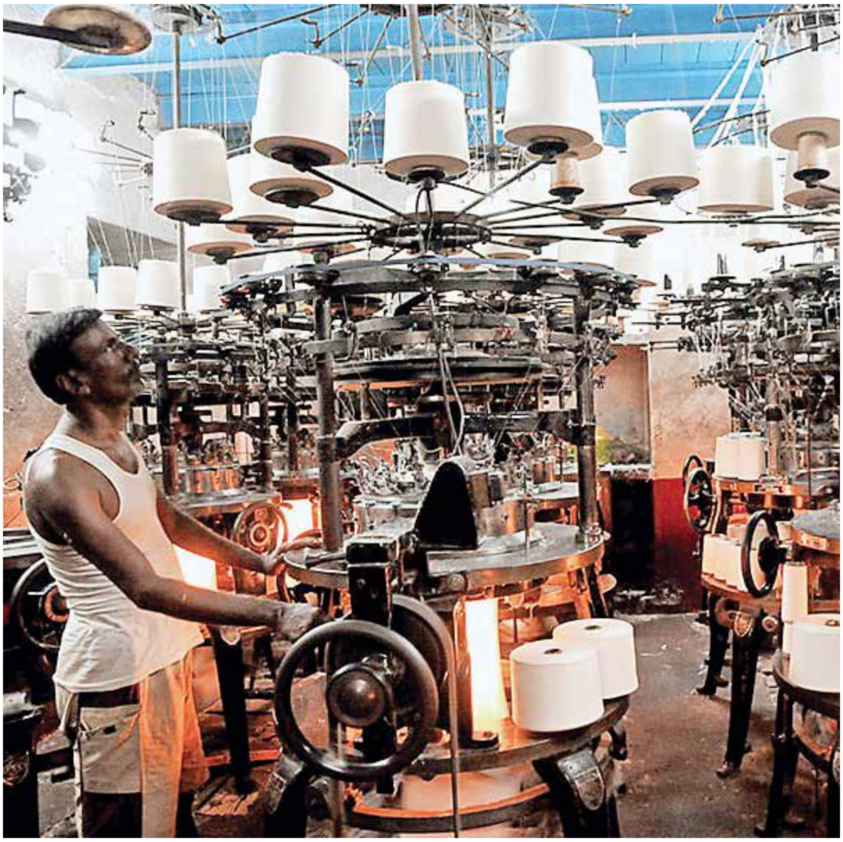

> **छोटे दुकानदारों और अन्य छोटा-छोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में इस योजना से काफी मदद मिली है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक अभाव की वजह से खुद का कारोबार शुरू नहीं कर पाते।**

तीसरे कार्यकाल में मुद्रा लोन की राशि को दोगुना कर 20 लाख रुपये कर दिया है।

पीएम मुद्रा योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब से यह योजना शुरू हुई है, तब से लेकर 18 अक्टूबर, 2024 तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत 30.36 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए हैं, जबकि 31.09 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को स्वीकृति दी गई है। इस योजना से 50.13 करोड़ से अधिक छोटे और नए उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में शिशु कैटेगरी के तहत 4.30 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन स्वीकृत किए गए जो उस वर्ष कुल मुद्रा लोन की संख्या का 69.13 प्रतिशत था। इस कैटेगरी के तहत 1.41 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए जो कुल वितरण का 31 प्रतिशत था। इसी तरह, किशोर कैटेगरी के तहत स्वीकृत आवेदनों की संख्या 1.79 करोड़ रही जो कुल संख्या का 28.75 प्रतिशत था। इस कैटेगरी में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन का वितरण किया गया जो कुल वितरण का 45 प्रतिशत था। तरुण कैटेगरी के तहत 13.16 लाख आवेदन मंजूर हुए जो कुल आवेदन का 2.12 प्रतिशत था। तरुण कैटेगरी के तहत डिस्बर्स लोन की राशि 1.07 लाख करोड़ रुपये रही जो कुल वितरण का 24 प्रतिशत है।

छोटे दुकानदारों और अन्य छोटा-छोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने में इस योजना से काफी मदद मिली है। यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक अभाव की वजह से खुद का कारोबार शुरू नहीं कर पाते। ऐसे लोग इस योजना के तहत कर्ज लेकर खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं और पहले से चल रहे अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं।

किसे मिलेगा फायदा

पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन की तीन कैटेगरी होती है। शिशु, किशोर और तरुण। पहली बार लोन के लिए आवेदन करने वाले को शिशु कैटेगरी में रखा जाता है और उन्हें 50 हजार रुपये तक का लोन दिया जाता है। शिशु लोन चुकाने के बाद आवेदक दूसरे वर्ष किशोर लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन चुकता करने के बाद तीसरे वर्ष तरुण लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। तरुण लोन का पुनर्भुगतान करने वाले अब तरुण प्लस कैटेगरी के तहत 20 लाख रुपये का मुद्रा लोन ले सकेंगे।

मुद्रा लोन की राशि दोगुनी करने के केंद्र सरकार के फैसले से केवल स्वरोजगार को ही और अधिक बढ़ावा नहीं मिलेगा, बल्कि भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में भी यह योजना काफी मददगार साबित होने वाली है। ■

मेरा युवा भारत: युवाओं का बढ़ेगा सामर्थ्य

आशुतोष मिश्र

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। वर्तमान में देश की 37 करोड़ से ज्यादा यानी 27 फीसदी से अधिक आबादी 15 से 29 वर्ष तक की है। ऐसे में देश की युवा शक्ति को आगे बढ़ने की राह दिखाने और उन्हें राष्ट्रीय विकास का संवाहक बनाने के लिए केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास पर फोकस कर रही है। युवाओं के लिए कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर सुलभ कराने की घोषणा वित्त 2024-25 के बजट में की गई थी। अब सरकार ने 'मेरा युवा भारत (माई भारत)' नामक डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से इसकी शुरूआत कर दी है। माई भारत पोर्टल (https://www.mybharat.gov.in/) पर कॉलेज के छात्र खुद ही इंटर्नशिप के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसी पोर्टल पर उन्हें पता चल जाएगा कि कहां-कहां पर उनके लिए अवसर हैं। इस प्लेटफॉर्म से अब तक 1.55 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं।

यह पोर्टल युवाओं को उनकी क्षमताओं में सुधार और बेहतर बनाने का एक मंच देगा। इसका लक्ष्य सरकार के संपूर्ण दायरे में युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाने हेतु समान अवसर प्रदान करना है। यहां

'माई भारत' पोर्टल पर युवाओं को करियर काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग एवं वैकेंसी सहित मिलेगी सभी जानकारियां

'मेरा युवा भारत' मंच युवाओं के नेतृत्व में विकास के लिए सुविधाप्रदाता के रूप में काम करेगा

युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। युवा अपने विचारों और योजनाओं को भी इस पर साझा कर सकते हैं। उनके विचारों और अनुभवों का फायदा सरकारी योजनाओं को और बेहतर बनाने में किया जाएगा।

देश भर के युवा माई भारत पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न अवसरों और खेल आयोजनों के लिए नाम दर्ज कर सकते हैं। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 1.55 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। अब वे सरकार की नई योजनाओं व अपने अनुभवों को कॉलेज छात्रों के साथ साझा करेंगे। युवाओं को इस महत्वपूर्ण स्कीम (मेरा युवा भारत) से जोड़ने के लिए ये युवा वॉलंटियर्स देश भर के कॉलेजों में जाएंगे, जहां वे छात्रों को विकसित भारत के दृष्टिकोण और उसमें युवाओं की भूमिका के बारे में बताएंगे।

इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में देश के पांच हजार कॉलेजों में जल्द ही वॉलेंटियर्स की टीम भेजी जाएगी। इस पोर्टल पर देश के युवाओं को करियर काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार (वैकेंसी) के अवसरों की हर एक जानकारी सुलभ होगी।

सरकार का कहना है कि माई भारत प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा और आने वाले समय में इस पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि युवाओं को आसानी से करियर विकास और कौशल में बढ़ोतरी के अवसर मिलेंगे और उनका भटकाव दूर होगा। यह पोर्टल युवाओं को इंडस्ट्री, सरकार और स्वयं सेवी संगठनों (एनजीओ) में सीखने के अवसरों से जोड़ेगा। मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण मंच बनाना है। युवाओं में नेतृत्व विकास पर केंद्रित इसके उद्देश्यों में शामिल हैं:

- युवाओं को अलग-अलग भौतिक गतिविधियों के अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में सुधार करना।
- युवाओं को सामाजिक अन्वेषक और समुदायों का अगुआ बनाने के लिए उनमें निवेश करना।
- युवाओं की आकांक्षाओं और समुदाय की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल।
- सरकार के मौजूदा युवा केंद्रित कार्यक्रमों के समन्वय के माध्यम से युवाओं की दक्षता में वृद्धि।
- युवा वर्ग और मंत्रालयों के बीच वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना।
- एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस तैयार करना।
- सरकारी पहलों और युवाओं के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में सुधार।
- भौतिक और डिजिटल अनुभवों का मिश्रण-फिजिकल इकोसिस्टम बनाकर पहुंच सुनिश्चित करना।

पोर्टल से ऐसे जुड़ें युवा

देश भर के युवा माई भारत पोर्टल (https://www.mybharat.gov.in/) पर पंजीकरण करके पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न अवसरों और आयोजनों से जुड़ सकते हैं। यह पोर्टल तेजी से युवा विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है, जो पुलिस, शहरी स्थानीय निकायों और विभिन्न मंत्रालयों के साथ विविध अवसरों, कार्यक्रमों और स्वयंसेवी गतिविधियों की पेशकश करता है। यह मंच उभरते क्षेत्रों में अपनी पहुंच को व्यापक बनाने तथा शैक्षणिक संस्थानों और युवा संगठनों के साथ अपनी सहभागिता को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। माई भारत अपने विकास का सिलसिला जारी रखते हुए युवाओं के बीच समान अवसर प्रदान करने और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा युवा भारत का लक्ष्य मौजूदा कार्यक्रमों को एकीकृत करके, उपलब्ध संसाधनों और विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करके दक्षता बढ़ाना है। ■

युवाओं से संबंधित योजनाएं

- ❑ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- ❑ युवा लेखकों को सलाह देने के लिये युवा प्रधानमंत्री योजना
- ❑ समेकित बाल विकास सेवा योजना
- ❑ राष्ट्रीय युवा नीति- 2014
- ❑ राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम योजना

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives, Always!

LIFIC

LINAC-NCDC FISHERIES BUSINESS INCUBATION CENTER (LIFIC)

For Cooperatives as Fisheries Bussiness

Set up by NCDC at LINAC
under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)
Department of Fisheries,
Ministry of Fisheries, AH & D, Govt of India

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
National Cooperative Development Corporation
Ministry of Cooperation, Govt of India

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
IFFCO
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO KISAN DRONE
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"